

रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(प्रसाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 3 नवम्बर, 1979/12 कार्तिक, 1981

हिमाचल प्रदेश सरकार

खात्र एवं आपूर्ति विभाग

आदेश

शिमला-१७९००२, २६ अक्टूबर, १९७६

संख्या एफ०डी०एस०डी०(६)(६)१/७८.—इस विभाग के आदेश संख्या एफ०डी०एस०डी०(६)(६)१/७८, दिनांक ११-१०-७६ जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी किये जए आदेश संख्या जी०एस०ग्रार०(५३६)इ/इ०एस०एस०कोम०/सुगर, दिनांक १२-६-७६ को हिमाचल राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु जारी किया गया था का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार के आदेश संख्या जी०एस०ग्रार० ५४६ (ई) इ०एस०एस०/कोम०/सुगर, दिनांक २०-६-१९७६ को पुनः सामान्य बनता की सूचना के लिये हिमाचल राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

हस्ताक्षरित,
सचिव।

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION
(DEPARTMENT OF FOOD)**

ORDER

New Delhi, the 20th September, 1979

G.S.R. 546 (E)/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Sugar (Price Control) Order, 1979, namely:—

1. This Order may be called the Sugar (Price Control) Amendment Order, 1979,
2. In the Sugar (Price Control) Order, 1979 in Schedule I, in the Note, for Item (i), the following shall be substituted, namely:—
“(1) the duty of excise, the additional duty of excise in lieu of Sales tax and special duty of excise;”.

[No. 1-33/79-SPY (Desk-II)]

C. N. RAGHAVAN,
Joint Secretary.

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-१७९००२, ३० अक्टूबर, १९७९

सं० गृह (ए)-एफ(१३)२/७८.—यतः भूमि अर्जन अधिनियम, १९६४ (१९६४ का पहला एकट) के अन्तर्गत भारतीय संघ के लिये भूमि अर्जन करने के केन्द्रीय सरकार के कार्य भारतीय विधान के अनुच्छेद २५८ के खण्ड (१) के, अन्तर्गत भारत सरकार, गृह मन्त्रालय ने अधिसूचना संख्या एफ० २५(५)५७/१/११, दिनांक २० फरवरी, १९७९ जारी कर राज्य सरकार को सौंप दियी है;

और यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि संघीय कार्य के लिये सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः आमूचना व्यूरो जिला मुख्यालय के लिये आवास बनाने हेतु, भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतेव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त पुरक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरण में विविर्दिष्ट किया गया है, उपर्युक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, को जानकारी के लिये भूमि अर्जन अधिनियम, १९६४ की धारा ४ के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके में किसी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्य करने के लिये सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

कोई भी ऐसा हित वद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेप में कोई कथित भभि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीम दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, केलांग के ममक्ष अपनी आपनि दायर कर सकता है।

विनिर्देश

क्षेत्र

ज़िला	ग्राम	खसरा संख्या	बीघा	बिमवा	विसवांसी
लाहोल-स्पिति	केलांग कोठी कुमरांग।	५११	१	१३	—
		कुल जोड़ ..	१	१३	—

एल० एच० तोच्छांग,
मुख्य सचिव।

**GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(C-SECTION)**

NOTIFICATION

Simla-171002, the 29th October, 1979

No. GAD(PA)-5(E)2/77-CC.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to accord sanction to the extension of the period of submission of the final report to the State Government by Shri J.C. Malhotra, Emergency Excesses Inquiry Authority, appointed *vide* Resolution No. GAD (PA)-5(E)-2/77-CC, dated the 25th July, 1978, upto 31st December, 1979.

2. The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to accord sanction to the extension of the period upto 31st December, 1979 for the submission of the final report to the State Government by Shri P. P. Srivastava Emergency Excesses Inquiry Authority appointed *vide* Resolution No. GAD(PA)-5(E)-2/77-CC, dated the 28th August, 1978,

3. This Notification is in continuation of this Department notification No GAD(PA)-5(E)-2/77-CC, dated 29-9-78, 10-1-79, 24-2-79 and 18-5-79.

L. HMINGLIANA TOCHHAWNG,
Chief Secretary

पंचायती राज विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला, ३१ अक्टूबर, १९७९

सं. पी० सी० एच-एच० ए० (४)-३०।७६-II.—हिमाचल प्रदेश सरकार, स्थानीय स्वायत् शासन विभाग की अधिसूचना संख्या एल०एस०जी-ए० (४) २/७५, दिनांक २१-६-७९ जिसके अनुसार दौलतपुर

चौक, ज़िला ऊना की अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, के फलस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उप-धारा (२) धारा (४) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम १९६८ (१९७० का १९८०) अधिनियम में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम दौलतपुर चौक की ग्राम सभा दौलतपुर, विकास खण्ड गगरेट, ज़िला ऊना से सहर्ष अपवर्जित करते हैं जिसे अब अधिसूचित क्षेत्र दौलतपुर में सम्मिलित किया गया है। प्रधान, उप प्रधान तथा पंच जो ग्राम दौलतपुर चौक से ग्राम पंचायत दौलतपुर के लिये निर्वाचित हुए हैं अपने पद पर नहीं रहेंगे क्योंकि वे अब ग्राम सभा दौलतपुर चौक के हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, १९६८ की उप-धारा (५) धारा ६ के अधीन प्रधान, उप-प्रधान तथा पंच नहीं हैं।

शिमला, ३१ अक्टूबर, १९७६

संख्या पी० सी० एच-एच० ए-(४)-३०/७६- I.—हिमाचल प्रदेश सरकार, स्थानीय स्वायत शासन विभाग की अधिसूचना संख्या एल० एस०जी० ए० (४) २/७५, दिनांक २१-६-१९७६ जिसके अनुसार गगरेट, ज़िला ऊना को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, के फलस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उप-धारा (२) धारा (४) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, १९६८ (१९७० का १९८० अधिनियम) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्राम गगरेट को ग्राम सभा गगरेट, विकास खण्ड गगरेट, ज़िला ऊना से तथा ग्राम कलोह को ग्राम सभा कलोह, विकास खण्ड गगरेट ज़िला ऊना से सहर्ष अपवर्जित करते हैं जिन्हें अब अधिसूचित क्षेत्र गगरेट में सम्मिलित किया गया है। प्रधान, उप-प्रधान तथा पंच जो ग्राम गगरेट से ग्राम पंचायत गगरेट के लिये तथा ग्राम कलोह से ग्राम पंचायत कलोह के लिये निर्वाचित हुए हैं अपने पद पर नहीं रहेंगे क्योंकि वे अब ग्राम सभा गगरेट तथा ग्राम सभा कलोह के हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, १९६८ की उप-धारा (५) धारा ६ के अधीन प्रधान, उप-प्रधान तथा पंच नहीं हैं।

आदेश से,
अनंत पाल,
सचिव ।